

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 17 अगस्त, 2007.
विषय: उत्तराखण्ड राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना हेतु
वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कार्यालय ज्ञाप संख्या 51/07/XIX-2/2006, दिनांक 22 फरवरी, 2007 द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में उपभोक्ता क्लब के संचालन हेतु राज्य सरकार की ओर से अध्यक्ष, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, देहरादून को नोडल अधिकारी/एजेंसी नामित किया गया है। उक्त के क्रम में यह अवगत कराया जाना है कि भारत सरकार, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आदेश संख्या 11011/52/2006-सीडब्ल्यूएफ दिनांक 13 जून, 2007 द्वारा प्रदेश के 13 जनपदों के 100 विद्यालयों, जिनकी सूची संलग्न है, में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना हेतु कुल ₹0 10,00,000.00 (रुपये दस लाख मात्र), (₹0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) प्रति उपभोक्ता क्लब की दर से) की धनराशि अनुदान के रूप में अवमुक्त की गई है। भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई उक्त धनराशि के उपभोग हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना हेतु ₹0 10,00,000.00 (₹0 दस लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय हेतु आपके निर्वहन पर रखने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराई गई 13 जनपदों के विद्यालयों की संलग्न सूची के अनुसार प्रति उपभोक्ता क्लब ₹0 10,000/- की दर से भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी संलग्न दिशानिर्देशों के अनुरूप व्यय की जायेगी।
2. वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।
4. यह सूचित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जायेगा जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग किये जाने के लिये यह सुनिश्चित करें कि धनराशि को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय, तथा व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बीएम-13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"3456- सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनागत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0103-विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना -20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 774/वि0अनु0-5/2007 दिनांक 14 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:उपर्युक्त।

भवदीय,
(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या 5244-1(1)/ 07-XIX-2/36 खाद्य/2004, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 11011/52/2006-सीडब्ल्यूएफ दिनांक 13 जून, 2007 के संदर्भ में।
3. आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून।
5. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या 62528-30/8(16)/उपभोक्ता क्लब/06-07, दिनांक 12 फरवरी, 2007 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि राज्य के उक्त प्रस्तावित राजकीय इण्टर कालेजों में उपभोक्ता क्लब स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश अपने स्तर से जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला विद्यालयीय शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निबन्धक, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, खाद्य गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त अनुभाग-5/खाद्य अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।